

# बगैर नंबर वाहन चलाने का फैशन बेरोकटोक जारी

लूट एवं हत्याओं में हो रहा उपयोग, एक भी रेत वाहन पर नंबर नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 जनवरी। पन्ना जिले में इस समय बिना नंबर के वाहन चलाना फैशन बन चुका है। बिल्डिंग मटेरियल विशेषकर रेत, पत्थर एवं गिट्टी लदे 90 प्रतिशत ट्रक एवं डम्परों में कहीं नंबर नहीं रहता है। जबकि हद्दसे आये दिन हो रहे हैं। यदि इन रेत, गिट्टी एवं पत्थर भरे वाहनों से कहीं भी कोई हद्दसा होगा तो लोग बे मौत मारे भी जाएंगे और हद्दसा करने वाले वाहन घटना कर चले भी जाएंगे।

लेकिन नंबर न होने से चिन्हित



कर पाना मुश्किल भरा काम है। जिसके कारण घटनाकारित करने वाले वाहन पर कार्यवाही ही सम्भव नहीं होता और अज्ञात वाहन के नाम पर ही मामला दर्ज होता है। इसके



अलावा दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में नंबर प्लेट तो लगी है पर उसमें नंबर प्लेट तो लगी है पर उसमें नंबर नहीं डलवाए गए। जबकि प्लेट प्लेट में नंबर डलवाये गए। जबकि प्लेट में नंबर डलवाने में 50 से 100 रूपये का खर्च आता है। उसके बाद भी वाहन चालक वाहनों में नंबर डलवाना मुनासिब नहीं समझते।

शहर में यातायात पुलिस द्वारा यदाकदा जब चेकिंग अभियान चलाया जाता है तो बगैर नंबर के वाहन चलाने के शौकीन लोग इधर उधर से भागना ज्यादा मुनासिब समझते हैं और यातायात पुलिस



द्वारा समय समय पर कार्यवाही एवं जुर्माना भी किया जाता है लेकिन इसके बावजूद भी वाहनों पर नंबर नहीं डलाने के पीछे का मकसद साफ है कि नंबर दो का कारोबार इन वाहनों से संचालित होता है। इसी कारण नंबर डालना उचित नहीं समझते हैं। चेकिंग के दरम्यान जो वाहन पुलिस की पकड़ में आ जाते हैं वे इधर उधर से दबाव बनाकर आजाद हो जाते हैं। इन्हें पुलिस द्वारा वाहनों में नंबर डलवाने के समझाशा दी जाती है। इस समझाशा के बाद भी शहर में बगैर नंबर के वाहनों की संख्या कम नहीं हो रही है। बल्कि दिनोंदिन बगैर

नंबर के वाहनों संख्या में इजाफा होता जा रहा है जिनके द्वारा आए दिन लूट एवं अपहरण की घटनाएं हो रही हैं। यह पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि उक्त वाहन आखिर है कहां का। बताते हैं कि बगैर नंबर के वाहनों की आड़ में

शहर में चोरी के वाहन भी दौड़ रहे हैं।

इसके लिये बेहद जरूरी है कि एक ऐसा अभियान चलाया जाय कि जिससे बगैर नंबर के वाहनों चलाने वाले लोगों को नंबर डलवाने के लिये मजबूर होना पड़े।



## वन विभाग की तत्परता से जंगली सुअर का सफल रेस्क्यू

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 जनवरी। दक्षिण पन्ना वनमण्डल के मोहन्दा वन परिक्षेत्र अंतर्गत सिंगवारा बीट में एक जंगली सुअर के आबादी क्षेत्र की ओर भटक आने की सूचना प्राप्त होने पर वन विभाग द्वारा तत्काल रेस्क्यू कार्रवाई की गई।

परिक्षेत्र सहायक कोटी

नरपाल सिंह के मार्गदर्शन में विभागीय दल मौके पर पहुंचा और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित एवं मानवीय तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित किया गया। इस अभियान में बीट गार्ड पूर्व मोहन्दा जयप्रकाश नारायण दुबे, बीट गार्ड दमुईया आदि की सक्रिय भूमिका रही।

## समझौता के साथ सख्ती दिखाए पुलिस

शहर में बगैर नंबर वाहन दौड़ाने का जो फैशन चल गया है वह किसी भी लिहाज से सही नहीं है। जिसे में बेहद जरूरी है कि पुलिस विभाग सख्ती के साथ लोगों को वाहनों में नंबर डलवाने के लिये प्रेरित करे। पुलिस विभाग यदि एक लंबा अभियान चलाकर सख्ती दिखाए तो बगैर नंबर के वाहनों की संख्या कम होने के साथ ही चोरी के वाहनों के कुछ मामलों का खुलासा भी हो जाएगा।



## सांदीपनि गार्डन में हुआ 15 वां गहोई महोत्सव

नवभारत न्यूज

पवई/पन्ना 18 जनवरी। गहोई वैश्य पंचायत महिला एवं नवयुवक मंडल पवई के तत्वाधान में नगर के सांदीपनि गार्डन में 15 वें गहोई दिवस पर भव्य गहोई महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कमलेश सुहाने जिला अध्यक्ष भाजपा

मैहर, विशिष्ट अतिथि वद्री प्रसाद सरावगी, डॉ रमेश बेहरे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता गहोई वैश्य समाज पवई के अध्यक्ष गणेश डेगरे के द्वारा की गई। कार्यक्रम में चरित्रजनों एवं समाज के मेधावी छात्रों का सम्मान, सांस्कृतिक कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मान एवं पुरस्कार वितरण किया गया।

## अमानगंज में धूमधाम से मनाया गया 'गहोई दिवस'

अमानगंज/पन्ना 18 जनवरी।

स्थानीय गहोई वैश्य समाज अमानगंज के तत्वाधान में रविवार, 18 जनवरी को गहोई दिवस का भव्य आयोजन अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ सम्पन्न हुआ। नगर के रसाई मण्डपस्थ में आयोजित इस कार्यक्रम में समाज की एकजुटता और सांस्कृतिक विरासत को अनूठी झलक देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 9 बजे गहोई भवन से भव्य शोभा यात्रा के साथ हुई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए आयोजन स्थल तक पहुंची।

## विश्व शांति के लिए संत उमाकान्त महाराज की धार्मिक अपील सहित चेतावनी

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 जनवरी। सबकी भलाई चाहने वाले सबको शाकाहारी नशामुक्त बनाकर कुदरत के प्रकोप से बचाने वाले परम पूज्य परम सन्त बाबा उमाकान्त जी महाराज ने बताया कि खजुराहो में दो दिवसीय खलसंग व नामदान कार्यक्रम में देश के कोने कोने आए हुए श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए बताया कि स्वयं संकटों से बचना है और लोगों को बचाना है।

कोई भी देश घातक हथियार



नहीं बनाएगा यह समझोगे समझ जाए तो विनाश बचाकर विकास हो सकता है कुछ लोग तो ऐसा सोचते हैं लोग भर जाए कट जाए हमारी शान सत्ता कायम रहनी चाहिए विदेश के जिम्मेदार अगर

भारत को ऋषि मुनि संत महात्मा की धर्म भूमि पर आकर विश्व शांति की गोष्ठी करें तो बचत हो सकती है वरना आगे का समय विनाशकारी बचे वही जो नाम अधारी।

## धार्मिक अपील सहित चेतावनी

मरने और मारकाट करवाने

की बड़ी सख्त सजा मिलती है:- संत उमा कान्त जी महाराज ने देश हित की बात समझते हुए कहा कि हत्या - जीव हत्या की कमाई से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसी

कमाई से बचना चाहिए। बाबा जी ने सबको चेताया कि आप हुकूमत में हैं और जनता का विनाश करा दिया तो क्या आपको नहीं मालूम कि इसकी सजा नरकों में कटोरी यातनाएं सहनी पड़ती है।

## छोटा बन जाने पर महानता आ जाती है

उन्होंने कहा संगत के जिम्मेदारों को संगत के लोगों को यह बात बतानी चाहिए कि गुरु महाराज पहले हाथ जोड़ते थे फिर आप जोड़ते थे। उन्होंने हाथ जोड़ना, प्रणाम करना सिखाया, छोटा बन जाने पर महानता आ जाती है। और गृहस्थ का धर्म समझाते हुए कहा - कोई भूखा प्यासा है। आपके दरवाजे पर आ गया, आ जाए उसको खिलाओ पिलाओ। अपने से अच्छे स्थान पर बैठोअच्छी व्यवस्था करो।

## सरकार की गारंटी पर मिलेगा मेधावी छात्रों को बैंक ऋण

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 जनवरी। निम्न आय वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है क्योंकि बैंकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक ऋण प्राप्त करने पर कोलेट्रल सिक्क्युरिटी मांगी जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश अनुसार वर्तमान में उच्च शिक्षा के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने पर 4 लाख रूपये तक के ऋण के लिए किसी प्रकार की कोलेट्रल सिक्क्युरिटी की आवश्यकता नहीं होती। इससे अधिक राशि के ऋण के लिए बैंक द्वारा कोलेट्रल सिक्क्युरिटी लिये जाने का प्रावधान है। निम्न आय वर्ग के विद्यार्थियों के परिवार द्वारा

उनके पास भूमि भवन आदि नहीं होने से कोलेट्रल सिक्क्युरिटी दी जाना संभव नहीं होता है। ऐसे गरीब मेधावी विद्यार्थी जिन्हें उच्च शिक्षा के लिए ऋण की आवश्यकता है उन्हें इस योजना से राज्य सरकार की गारंटी पर बैंकों से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। योजना का नोडल विभाग संस्थागत वित्त है।

**पांच लाख से अधिक न हो परिवार की वार्षिक आय:-** उच्च शिक्षा के लिए गारंटी योजना में ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जिनके परिवार की सभी स्त्रियों से वार्षिक आय 5 लाख रूपये से अधिक न हो। विद्यार्थी को बैंक से ऋण के लिये आवेदन संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार

करना होगा। साथ ही कोलेट्रल सिक्क्युरिटी के लिए शासकीय प्रत्याभूमि जारी करने के लिए निर्धारित प्रारूप में दस्तावेजों के साथ पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। विद्यार्थी अपने महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। विद्यार्थी बैंक के माध्यम से संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी को आवेदन पत्र समित करेंगे। विद्यार्थी संबंधित विभाग के नोडल अधिकारी की सीधे आवेदन पत्र देगा। उच्च शिक्षा ऋण के लिए गारंटी योजना में विद्यार्थियों के चयन के लिए योजना का क्रियान्वयन करने वाले विभागों में छानबीन समिति गठित

की गई है। छानबीन समिति विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम की गुणवत्ता शिक्षण संस्थान की मान्यता, विद्यार्थी के पालक की आर्थिक स्थिति पाठ्यक्रम में

विद्यार्थी के चयन की प्रक्रिया, विद्यार्थी द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की वापसी की संभावना का मूल्यांकन के आधार पर योजना के लिए विद्यार्थी का चयन करेगी।

## संख्या का निर्धारण वित्त विभाग करेगा

योजना का क्रियान्वयन तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष् एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। योजना में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उच्च शिक्षा के लिये ऋण प्राप्त करने के लिए शासन के तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, आयुष् एवं उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उनसे संबंधित अधिसूचित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के लिए गारंटी दी जायेगी। इत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 200 विद्यार्थियों के प्रकरणों के लिए गारंटी दी जा सकेगी। विभागावार विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण के लिए दी जाने वाली गारंटी की संख्या का निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया गया है। इसमें विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण भी सम्मिलित रहेंगे। परंतु ऐसे विद्यार्थियों की संख्या विभाग के लिए निर्धारित संख्या की कुल संख्या के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

## जनता का एक करोड़ पानी में, नए बस स्टैंड के लिए नगरपालिका को फिर चाहिए नई जगह

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 जनवरी। शहर का इकलौता प्राणनाथ बस स्टैंड दबाव के कारण छोटा पड़ रहा है। इस समस्या से निजात दिलाने 10 साल पहले बायपास स्थित कमला बाई ताल के नजदीक नया बस स्टैंड बनाने जमीन आवंटित की गई।

वहां समतलीकरण किया गया, अतिक्रमण हटाए गए, साफ सफाई कराई गई और सीसी सड़क बनाने सहित अन्य कार्य में 1 करोड़ से अधिक की

राशि खर्च हुई। अब नगर पालिका बस स्टैंड बनाने जिला प्रशासन से दूसरी जमीन मांग रहा है। नगर पालिका परिषद का 19 दिसंबर को साधारण सम्मेलन हुआ। इसमें नये बस स्टैंड के लिए जमीन आवंटन की स्वीकृति सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में नया बस स्टैंड बनाने का सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही बस स्टैंड बनाने के लिए गौशाला की जमीन को लेकर चर्चा की गई, जबकि पूर्व से आवंटित कमलाबाई ताल की

जमीन पर दो मिनट चर्चा नहीं हो सकी। जबकि जिला प्रशासन ने कमलाबाई तालाब के पास बस स्टैंड के लिए आवंटित जमीन में अवैध अतिक्रमण भी हटवाया था। तब काफी वाद विवाद भी हुआ था। वहां सीसी सड़क भी बनवाई गई। 10 साल में बस स्टैंड शिफ्ट नहीं हो पाया।

**प्राणनाथ बस स्टैंड में नहीं पर्याप्त जगह:-** प्राणनाथ बस स्टैंड में जितनी बसों का संचालन होता है, उसके अनुसार उन्हें खड़ा करने का स्थान ही पर्याप्त नहीं है। ऐसे में चालक आड़ी तिरछी बसे

खड़ी करते हैं तो यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर का यातायात भी बाधित होता है इसी कारण ही नवीन बस स्टैंड की लंबे समय से

मांग की जा रही है। जमीन आवंटन के 10 साल बाद भी बस स्टैंड को शिफ्ट नहीं किया गया। इसे बस स्टैंड में आए दिन विवाद के हालात बनते हैं।

## गौशाला को शिफ्ट करने का प्रस्ताव

नगर पालिका के जिम्मेदार अब छतरपुर अजयगढ़ बायपास स्थित गौशाला को सिमरा गांव में शिफ्ट कर गौशाला में बस स्टैंड बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। नगर पालिका के अमले ने इसका पूरा कामजी खाका तैयार लिया है। वहां नये सिरे से सीसी रोड, समतलीकरण सहित अन्य कार्य किए जाएंगे, जहां जनता लाखों रूपये रिफ खर्च होंगे। जबकि पुरानी जगह पर एक करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं।

मौन:- पन्ना की आम जनता खाद्य सामग्री, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और अन्य जरूरी सामान उच्च दामों पर खरीदने के लिए मजबूर है। मध्यम और निम्न वर्ग के परिवारों का घरेलू बजट पूरी तरह से बिगड़ चुका है। बावजूद इसके न तो नापतौल विभाग सक्रिय दिख रहा है और न ही खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग कोई

## मतदान केन्द्र स्तर पर भी मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस

पन्ना 18 जनवरी। आगामी 25 जनवरी को 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन मुख्य समारोह के अतिरिक्त मतदान केन्द्र स्तर पर भी किया जाना है। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रति मतदान केन्द्र 250 रूपये के मान से जिले के कुल 1004 मतदान केन्द्रों के लिए आवंटन उपलब्ध कराया गया है। यह राशि प्रत्येक बीएलओ को उनके वेतन से मैट्र बँक खात में अंतरित की जाएगी।



## नगर परिषद के सभागार में गणतंत्र दिवस मनाने को लेकर हुई तैयारी बैठक

नवभारत न्यूज

देवेन्द्रनगर/पन्ना 18 जनवरी। नगर परिषद देवेन्द्रनगर के सभागार में शिवांगी गुप्ता अध्यक्ष नगर परिषद की अध्यक्षता में एवं जय कुमार कुशवाहा उपाध्यक्ष के के तिवारी सीएमओ की उपस्थिति में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने हेतु बैठक आयोजित की गई। जिसमें एम एस बुंदेला उपयंत्री व पुण्य केशर द्विवेदी, ललित गुप्ता सहित समस्त शासकीय व अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के संस्था प्रधान उपस्थित रहे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि नगर परिषद देवेन्द्रनगर में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा व सामूहिक ध्वजारोहण शासकीय बालक हायर सेकेंडरी में सुबह 9 बजे से मुख्यअतिथि शिवांगी ललित गुप्ता के द्वारा किया जाएगा व मुख्यमंत्री जी के संदेश का वाचन किया जाएगा। नगर के विभिन्न शासकीय व अशासकीय विद्यालयों

के छात्र छात्राओं द्वारा मार्च पास्ट, शारीरिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे व झांकियों का प्रदर्शन होगा। व अंत में पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम सम्पन्न होगा। कार्यक्रम के दौरान समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय अधिकतम 10 मिनट निर्धारित किया गया है व देशभक्ति व सामाजिक संगीत पर ही कार्यक्रम दिए जाएं। एवं ध्वजारोहण एवं मार्च पास्ट में सरस्वती हायर सेकेंडरी विद्यालय का उद्घोष बैंड रहेगा एवं नगर परिषद एवं बालक हायर सेकेंडरी स्कूल समस्त व्यवस्था की देखरेख करेगा। समस्त संस्था प्रधान 24 जनवरी तक शासकीय बालक हायर सेकेंडरी में प्राचार्य कक्ष में शिक्षक विश्वनाथ प्रजापति, उदय पाल सिंह परमार को अपने कार्यक्रमों की सूची देवे। व नगर परिषद से मिशन हेतु 20 जनवरी तक छात्र संख्या भेज दें।

## जीएसटी औचित्यहीन साबित मनमाने रेट पर बेची जा रही बिना बिल के सामग्री

नवभारत न्यूज

पन्ना 18 जनवरी। भारत सरकार द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर ( जीएसटी) लागू कराते समय यह दावा किया गया था कि इससे टैक्स प्रणाली सरल होगी, व्यापार पारदर्शी बनेगा और सबसे बड़ा लाभ आम उपभोक्ता को मिलेगा। सत्ता पक्ष के नेताओं और

जनप्रतिनिधियों ने गली गली जाकर इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उलट नजर आ रही है।

रा क्षेत्र में आज भी आम जनता को जीएसटी का कोई वास्तविक लाभ मिलता नहीं दिख रहा, बल्कि इसे जनता को बहलाने वाला झुनझुना साबित किया जा रहा है।

खाद्य सामग्री से लेकर दैनिक उपयोग की वस्तुएं एमआरपी (अधिकतम खुदरा मूल्य) से भी उच्च दामों पर बेची जा रही हैं। नियमों के अनुसार किसी भी वस्तु को एमआरपी से अधिक मूल्य पर बेचना अवैध है, बावजूद इसके खुलेआम यह खेल चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे मामले में प्रशासन की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

एमआरपी पर थोक में सामान, रिटेलर मजबूर:- नाम न छापने की शर्त पर एक स्थानीय खुदरा व्यापारी ने बताया कि होलसेलर उन्हें सामान एमआरपी के बराबर कीमत पर थोक में दे रहे हैं। ऐसे में रिटेलर के सामने दो ही रास्ते बचते हैं- या तो घाटा उठाकर सामान

बेचें या मजबूरी में एमआरपी से ऊपर दाम वसूलें। व्यापारी का कहना है, जब हमें ही होलसेलर से अधिक मूल्य वसूलने वालों पर कार्यवाई कर सकता है, लेकिन अब तक सिर्फ औपचारिकताएं ही निर्भाई जा रही हैं। आम नागरिकों और व्यापारियों की मांग है कि एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्यवाई हो। मैनुफैक्चर

टोस कारवाई करता नजर आ रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि प्रशासन चाहे तो एमआरपी से अधिक मूल्य वसूलने वालों पर कार्यवाई कर सकता है, लेकिन अब तक सिर्फ औपचारिकताएं ही निर्भाई जा रही हैं। आम नागरिकों और व्यापारियों की मांग है कि एमआरपी से अधिक मूल्य पर बिक्री करने वालों पर सख्त कार्यवाई हो। मैनुफैक्चर

कंपनी, होलसेलर और डीलर की जांच की जाए। नियमित रूप से बाजार निरीक्षण किया जाए। दौषियों पर जुर्माना और लाइसेंस निरस्तोकरण जैसी कार्यवाई हो। यदि समय रहते प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, तो जीएसटी के नाम पर आम जनता से होने वाला यह छलावा और भी गहरा होगा, और अच्छे दिन केवल नरों तक ही सीमित रह जाएंगे।

## जीएसटी हटते ही सस्ता, फिर अचानक महंगाई

स्थानीय व्यापारियों के अनुसार,

जैसे ही जीएसटी समाप्त या कम हुआ, एक सप्ताह तक बाजार में सामान सस्ते दामों पर उपलब्ध हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कीमतें कम हो सकती हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद दाम फिर से आसमान छूने लगे। यह स्थिति इस बात का संकेत है कि कीमतों में बढ़ोतरी का कारण टैक्स नहीं, बल्कि मुनाफाखोरी और सांटागैट है।